नहीं है। वह जानना चाहते हैं कि ऐसी कोई शिकायत आई है या नहीं।

Shri T. T. Krishnamachari: I have no personal knowledge of it.

श्री हुकम चन्द कछवाय । मैं यह चाहता हं कि सामान्य तौर पर श्रभी तक इलाजों के लिये कितनी विदेशी मुद्रा दी है भीर कितने लोगों को दी है।

प्रध्यक्ष महोदय: सामान्य तौर पर किन लोगों को दी है, ऐसी कोई इन्फार्मेशन है मया ।

श्री हकम चन्द्र कछवाय : लोगों के लिये नहीं।

सप्यक्ष महोदय : श्रांखों के इलाज के लिये सामान्य तौर पर कितना दिया गया है।

भी ब रा० भगतः इस की तफसील के लिये सूचना चाहिये।

Dr. Sarojini Mahishi: I am resricting my question to part (a) of this Question. May I know whether any discrimination is made in allowing foreign exchange between an ordinary citizen going for Haj and a V.I.P. going for Haj? For example, the amount allowed to Sheikh Abdullah in this matter....

Mr. Speaker: He did not go for an eye operation. Next Question.

Shri Kapur Singh: Sir, before we pass on to the next Question, will you permit us to put on record that in whatever questions have been put here there has been no intention whatsoever of importing any suggestion that we took any exception to the arrangements that were made in connection with the eye operation of our President.

India's Credit to Foreign Countries.

Shri Raghunath Singh: Shri P. C. Borocah: Shri Madhu Limaye: Shri Rameshwar Tantia: Shri Tula Ram: *1085. ∠ Shri Vishwa Nath Pandey: Shri Murli Manchar: Shri Ram Harkh Yadav: Shri Koya: Shri Brij Basi Lal: Shri Kanakasabai:

11774

Will the Minister of Finance be pleased to state:

- (a) whether Government have decided to provide some credit to Nepal, Ceylon and Sudan in order to assist them in setting up industrial units;
- (b) if so, the amount of credit to each country; and
- (c) the particulars of the projects to be financed therewith?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) Yes, Sir.

- (b) The amount is Rs. 1 crore for Nepal and Rs. 5 crores each for Sudan and Ceylon,
- (c) A formal loan agreement was signed with the Royal Nepalese Government, providing a credit of Rs. 1 crore on 29th September, 1964. discussions with the Government of Ceylon and the Government of Sudan will be taken up shortly to finalise the credit arrangements.

भी रघुनाच सिहः मैं जानना चाहता हं कि यह जो रुपया दिया गया है क्या वह किसी प्लेन के लिये दिया गया है, भीर जो रुपया दिया जायेगा, वह काइन्ड में दिया जायेगा या कैश में दिया जायगा।

श्री व रा भगत: प्रभी तक तो कोई रुपया नहीं दिया गया है। लेकिन भ्रागे जो दिया जायेगा उस से महां से कैपिटला इक्विपमेंद्रस भेजे जायेंगे।

श्री रचुनाच सिंह: यह रुपया किसी योजना के लिये दिया जायेगा या किसी श्रीर काम के लिये दिया जायेगा ।

श्री दि० रा० भगतः : यह उन देशों में इंडस्ट्रीज की स्थापना के लिये या उद्योगों को प्रोत्साहन देने के कामों के लिये दिया जायेगा। जो स्कीम भ्रायेगी उस के मुताबिक होगा।

Shri P. C. Borocah: May I know whether it is a fact that under the concentrated scheme Indian collaborators will be allowed to participate in the capital structure of industrial units in these countries and also in the supply of capital goods, technical knowhow, etc. and, if so, what are the basic terms which have been laid down by the Government.

Shri B. R. Bhagat: As I said, the agreement has been signed with Nepalese Government. But no formal proposal, or scheme, has come. All this will be borne in mind when an individual scheme comes. If the Nepalese nationals want that in addition to this, they want some equity participation, it will depend in what form the proposals come.

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : जो धन नैपाल, सूडान श्रीर लंका को देने का सरकार विचार कर रही है उद्योगों की स्थापना के लिये, उस के सम्बन्ध में उन सरकारों ने भारत सरकार से प्रायंना की थी या कि भारत सरकार सृपने से दे रही है। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि इस के पहले क्या इन देशों को श्रीद्योगीकरण करने के लिये सरकार ने कुछ भीर सहायता दी है।

शां बं रा भगत : यह तो श्रापस की बात चीत के हिसाब से चलता है, श्रीर जैसा माननीय सदस्य को मालूम होगा अन्तर्राष्ट्रीय श्राधिक सहयोग में देश एक दूसरे की मदद करते हैं। भारत दूसरों की मदद करता है श्रीर दूसरों से मदद लेता है। अगर हम ऐसी स्थित में हैं कि पास पड़ीस

के देश को नददं दे सर्के तो हमारी सदा यह इच्छा रहती है कि हम उन्हें मदद करें। इसी विश्वास के साथ यह स्कीम चलती है।

श्री राम हरस यादव : मैं जानना चाहता हूं कि जो कर्जा दिया जा रहा है, कोसी प्रोजैक्ट भीर गंडक प्रोजैक्ट उस के ग्रलावा हैं या उसी में शामिल हैं।

श्री **व**ः **राः भगतः** कोसी श्रौर गंडक का सवाल ग्रलग है । यह वहां उद्योगों की स्थापना के लिये है ।

बी भागवत का बाजाव : मैं जानना चाहता हूं कि शतों में नया यह भी शतें है कि उन का स बन्ध योजना विशेष से होगा और उन के लिये भारतीय तकनीकी पर्सोनल भी जायेंगे या यह कर्ज मुक्त है भीर वे जिस प्रकार से और जहां चाहें खर्च कर सकते हैं। या उस कर्जे से जो सामान भारत में प्राप्त है वह उन को भेजा जायेगा।

श्री ब॰ रा॰ भगत: यह कर्ज उन चीजों को खरीदने के लिये हैं जो यहां से सामान भेजा जायेगा, खास कर कैंपिटल इक्विपमेंट । ग्रगर उस को लगाने के लिये वह सहायता मांगेंगे तो वह भी दी जायेगी।

श्री सरक् पाच्डेय: श्रभी मंत्री जी ने बतलाया कि जो देश पास पड़ौस के हिन्दुस्तान से पिछड़े हुए हैं

श्री ब॰ रा॰ भगतः : मैं ने पिछड़े हुए नहीं कहा ।

श्री सरक् पाण्डेय: मैं जानना चाहता हूं कि जब ग्रपना देश इतना पिछड़ा हुआ है तो ग्रपनी तरक्की न कर के पास पड़ौस के देशों की तरक्की करने की चिन्ता हमें ज्यादा क्यों रहती. है।

श्री रामेश्वरामण्य : मैं जानना चाहत ा हूं कि नैपाल ग्रीर दूसरे पड़ौसी देशों क रे जब भारत ऋण दे रहा है तो उन देशों थे पहले हम से कितना ऋण लिया है भीर भारत अर्घ के ऊपर कितना विदेशी ऋण है ?

श्री ब॰ रा॰ भगत: इस की मुझे सूचना मिले तो मैं बतला सकता हूं।

Shri P. Venkatasubbalah: It is very creditable on the part of Government to have come to the aid of our neighbouring countries, as a gesture of good-will. May I know whether the same aid will be extended to the other African countries which may enter into a contract with us for purchase of our machinery etc.?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): Including Pakistan.

Shri B. R. Bhagat: In addition to this, we have some arrangement with Uganda, Kenya, Ghana and Nigeria etc.

श्री शिकाजी राव शं० देशमुख: क्या मैं जान सकता हूं कि विदेश विकास के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में कोई धनराशि संरक्षित रक्खी गई थी या नहीं। ग्रगर नहीं तो यह ज्यय किस धन में से होता है।

श्री बि॰ रा॰ भगत: यह तो मुझे ज्ञात नहीं है कि तोसरी पंजवर्षीय योजना में कितनी राशि रक्खी गई थी।

श्री हुकम चन्द कछ राय : मैं जानना चाहता हूं कि हम विदेशों को जो ऋण देते हैं उस के लिये हम ने क्या कोई शर्त रक्खी हैं। उस पर कोई इंटरेस्ट मिलता है या नहीं और ग्रगर मिलता है तो कितना ?

श्री ब॰ रा॰ भगत: नेपाल से जो तय हुमा है वह पन्द्रह साल के लिये 3 प्रतिशत इंटरेस्ट है। बाकी दूसरे देशों से, जैसा मैं ने कहा, प्रभी एग्रीमेंट हुमा नहीं है। इस लिये उन के बारे में बतलाना मश्किल है।

श्री बज्ञपाल सिंह : इसी म्रादरणीय सदन में माननीय वित्त मंत्री जी ने बतलाया श्रा पिछले वर्षे कि पाकिस्तान की तरफ हमारा 9 घरब रु० कर्ज है। मैं जानना चाहता हूं कि उस 9 घरब रु० में से कितना रुपया बाकी है ग्रौर कितना वसूल हो चुका है।

ग्रध्यक्ष महोवय : वह ग्रलग सवाल है।

श्रीयज्ञपाल सिंह: इस में लिखा हुग्रा है। इस की हैडिंग में फारेन लिखा हुग्रा है। विदेशी ऋण।

भ्रष्टिक महोदय: वह ऋण दिया नहीं। भ्रगर कोई जबर्दस्ती ले कर बैठ जाये तो क्या किया जाये।

श्री यशपाल सिंह : वापस लिया है या नहीं ।

श्री हुकम अन्द कछ शाय: क्या हम ने उन से जबर्दस्ती वसूल किया है।

Shri Heda: May I know the procedure adopted when an Indian industrialist exports machinery from India to those countries for setting up industries there? May I know whether the price of that machinery is reimbursed to him out of this loan or whether that amount is kept in credit in his name and he is paid that amount only when the money comes back or is returned from those countries?

Shri B. R. Bhagat: This is not a supplier's credit; this is a government to government credit. So all those questions do not arise.

Shri Nath Pai: The aid-receiving countries, though needing aid, are often very sensitive and also suspicious, as we know from our own experience, and often aid is mistaken as a form of extension of influence, as has been shown by the way Burma and Indonesia rejected U.S. aid. May we know whether the conditions under which aid is being given are such as to ensure that these receiving countries feel that we are interested in their development, not in extending Indian influence or helping a few

Indian capitalists? Are these precautions being taken by the Finance Minister?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): That objective is always kept in view.

Demolition of Jlauggis

*1086. Shri Maurya: Will the Minister of Works and Housing be pleased to state:

- (a) whether two thousand lhuggis and jhoparies have been demolished since 1st April, 1965 in localities of Sarai Rohilla, Bhooli Bhatiyari and Wazirpura in Delhi;
- (b) whether it is a fact that some jhuggis and jhoparies were burnt by the demolishing squad and on resistance ladies and children were lathicharged:
- (c) whether the Prime Minister had given an assurance to the Republican leaders that the hut dwellers upto 31st December, 1962 will be provided alternate suitable site before demolition: and
- (d) whether it is a fact that jhuggis and Jhoparies referred to in part (a) above were in existence before December, 1962?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna): (a) No. The number of huts demolished was about 680.

- (b) No.
- (c) No. Under the Jhuggis and Jhoparies Removal Scheme, only those squatters are eligible for allotment of alternative accommodation who started squatting on Government and public lands prior to the 31st July, 1960. However, since eligible and ineligible squatters are inter-mixed in most of the localities Government is providing camping sites of 25 sq. yards even to ineligible squatters. These squatters are, however, not entitled to get plots of 80 sq. yards or built tenements.
- (d) The jhuggis and jhoparis in Serai Hohilla and Bhooli Bhatiyari had 496(Ai) LSD—2.

been constructed recently. Those in Wazirpur, were in existence before December 1962, but none of their occupants had census slips in proof of their occupation of the site prior to July, 1960.

श्री मीर्थ: श्रीमान्, ये झुग्गी झौंपड़ी निराकरण योजना के नोटिस जो झुग्गी झौंपड़ियों में रहते हैं उन को दे दिए जाते हैं, और तुरन्त ही झुग्गी झौंपड़ियों को तोड़ा जाता है, जैसा कि वजीराबाद में हुआ जहां सन् 1946 से लोग रह रहेथे। इन को तोड़ा ही नहीं जाता, बिल्क कहीं कहीं आग लगाने के भी सबूत मिले हैं, और बच्चों और औरतों को मारा पीटा जाता है। यह नोटिस मेरे हाथ में है। मैं इस को पढ़ कर नहीं सुनाना जाहता कि इस में क्या शर्त दी गयी हैं। पर उन को खाना बदोश बना कर ट्रांजिट कैम्प्स में रखा जाता है, वहां पर . . .

ग्रध्यक्ष महोदयः ग्राप का सवाल क्या है ?

श्री मौर्यं ः मैं यह कहना चाहता हूं कि जो झुग्गी झौंपड़ियां तोड़ी जाती हैं उन के लिए क्या मंत्री महोदय यह व्यवस्था करेंगे कि एक विशेष समय दिया जाए, श्रौर उस के बाद में उन को ट्रांजिट कैम्प्स में न रक्खा जाए बल्कि परमानेंटली उन को 80 गज का प्लाट ग्रलाट कर दिया जाए । प्रधान मंत्री जी ने हम से ऐसा वायदा किया था ।

श्री मेहर चन्य खन्ता : जहाँ तक प्रधान मंत्री के वायदे की बात है, वह सूचना गलत है। जहां तक झुन्गियों का सवाल है, मैं यह कह सकता हूं कि इस झुन्गी झींपड़ी स्कीम को हम हमदर्दी से चला रहे हैं। इन लोगों का..

श्री मौर्य: गलत बयानी मत करिये।

श्री नेहर चन्द सन्ना: मैं दिल्ली का रहने वाला ज्यादा जानता हूं या माननीय सदस्य जो धनीगढ़ के रहने वाले हैं ज्यादा जानते हैं।